दैनिक जागरण

दुविधा आत्मविश्वास में कमी के कारण उत्पन्न होती है

मोदी सरकार की दूसरी पारी

मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। इस पारी पर देश ही नहीं, दुनिया की भी निगाहें होंगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की है कि देश के साथ-साथ दुनिया भी दंग है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि इतने बड़े देश में कोई सरकार सत्ता विरोधी प्रभाव को दरकिनार करते हुए और अधिक मजबूती से सत्ता में वापसी करे। चूंकि इस बार भाजपा ने कई ऐसे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है जहां पिछली बार ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाई थी इसलिए यह तय है कि मोदी मंत्रिमंडल कुछ अलग तरह का होगा। ऐसा होना इसलिए भी तय है, क्योंकि अरुण जेटली सेहत के चलते सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को दुरुस्त करने के क्रम में दक्ष लोगों को ही मंत्री बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रियों की काबिलियत का ऊंचा स्तर ही चुनौतियों से पार पाने में सहायक बनेगा। इसमें संदेह नहीं कि मोदी सरकार की वापसी जनता के इस भरोसे के साथ हो रही है कि वह अपने पहले कार्यकाल में जो कुछ नहीं कर पाई उसे इस बार करेगी और साथ ही जो काम अच्छे से नहीं हो सके उनकी भी भरपाई हो सकेगी। स्पष्ट है कि इस बार मोदी सरकार से अपेक्षाएं और अधिक बढ़ी हुई होंगी। किसी भी सरकार के लिए इतनी विशाल आबादी की अपेक्षाएं पूरी करना आसान नहीं, लेकिन यह भी सही है कि जब बहुमत प्रबल होता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं।

यह अच्छी बात है कि आत्मविश्वास से भरे हुए प्रधानमंत्री यही आभास दे रहे हैं कि उन्हें जनता की बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा करना है। उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद अपने विभिन्न संबोधनों के जरिये ऐसे संकेत दिए हैं कि इस बार उनकी सरकार कुछ अलग तरीके से काम करेगी और पुराने कामों को गति देने के साथ ही कई बड़े लक्ष्य पूरे करने में भी जुटेगी। इनमें से कुछ का जिक्र भाजपा के घोषणा पत्र में भी है। चूंकि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अगले साल के अंत तक राज्यसभा में भी बहुमत हासिल कर लेगा इसलिए मोदी सरकार पर यह दबाव भी बढ़ेगा कि उसने जो चुनौती भरे वायदे किए हैं उन्हें अवश्य पूरा करे। इन वायदों को पूरा करने के साथ ही मोदी सरकार को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के अपने ध्येय को भी सार्थक साबित करना होगा। वास्तव में इससे ही देसी और विदेशी मीडिया के एक हिस्से की ओर से किया जा रहा कुप्रचार थमेगा। चूंकि देश ही नहीं दुनिया भी दूसरी पारी में मोदी सरकार को नए तेवर में देखना चाहेगी इसलिए यह अपेक्षित है कि नौकरशाही के तौर-तरीकों मे बदलाव को विशेष प्राथमिकता दी जाए। वास्तव में ऐसा करके ही नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकेगा। निःसंदेह यह अपेक्षा विपक्ष से भी है कि वह भी अपने पुराने तौर-तरीकों का परित्याग करे। लोकतंत्र में विपक्ष के सशक्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका रचनात्मक होना होता है।

कार्यशैली का सवाल

उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 18 साल बीत गए, बावजूद इसके लगता नहीं कि सरकारी विभागों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन आया हो। ताजा मामला परिवहन विभाग द्वारा वसूले जा रहे ग्रीन सेस का है। वर्ष 2012 से विभाग हर उस वाहन से सेस की वसूली कर रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन होना है। फिर चाहे वह दुपहिया हो या चौपहिया। खास बात यह है कि ग्रीन सेस इस उद्देश्य से लिया जा रहा है कि पर्यावरण को वाहनों के बढ़ते प्रदूषण से बचाया जा सके। सेस वसूली से सात साल में 80 करोड़ रुपये जमा हो गए, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। वजह भी यह कि नियमावली में विरोधाभास है। यह हैरत में डालने वाला ही है कि विभाग को नियमावली में खामी का पता भी अब चल रहा है। आखिर सात साल के अरसे में क्या एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि इन खामियों पर निगाह पड़ी हो। सवाल और भी हैं, मसलन नियमावली बनाते वक्त इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। यह अकेला मसला नहीं है। इसी से जुड़ा दूसरा मामला है सड़क सुरक्षा कोष का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर सुरक्षा कोष बनाया है। मकसद था कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए समिति इस कोष का उपयोग करे, लेकिन जब बात पैसे की आई तो शासन का मुंह ताकना पड़ा। अभी तक कोष में मात्र पांच करोड़ रुपये ही आए हैं, जबकि जरूरत 12 करोड़ की है। फिलहाल इसी पांच करोड़ से सड़क सुरक्षा से लेकर प्रदूषण जांच इत्यादि के कार्य किए जा रहे हैं। जाहिर है कि यदि नियमावली में विरोधाभास न होता तो 80 करोड़ की धनराशि का सदुपयोग किया जा सकता था। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दे विभाग की प्राथमिकता में जगह नहीं बना पाए हैं। दरअसल आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जूझ रहे प्रदेश में राजस्व के स्रोत बढ़ाना तो चुनौती है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है धन के सदुपयोग की। बजट खर्च करने के तौर-तरीकों से इसे समझा जा सकता है। सरकार द्वारा विभागों को आवंटित बजट में शामिल धनराशि को खातों तक पहुंचने से पहले लंबा 'सफर' तय करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका निदान सिर्फ पारदर्शी नीतियों और साफ नीयत से ही संभव है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और शासन इस दिशा में पहल करेंगे।

मोदी सरकार ने लिखी विकास की नई गाथा

धर्मेंद्र प्रधान

यह प्रचंड जीत मोदी सरकार की उन समावेशी नीतियों का परिणाम है जिसमें देश के सभी हिस्सों और खास तौर पर पूर्वी छोर को आजादी के बाद पहली बार बराबर का हक मिला

लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम भले ही राजनीतिक विश्लेषकों के लिए अप्रत्याशित रहे हों, लेकिन इस चुनाव ने भारत में राजनीति के परंपरागत तौर-तरीकों को नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया है। जाति-समीकरणों की बुनियाद पर टिके सियासी दल और उनकी स्वार्थपरक राजनीति न सिर्फ ध्वस्त हुई है, बल्कि पहली बार विकास की आकांक्षा से युक्त समाज ने सकारात्मक वोट कर मौजूदा सरकार को ही दोबारा जनादेश दिया। 2015 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर दिया गया पीएम मोदी का बयान कोई औपचारिकता भर नहीं था, बल्कि यह सरकार और उसके तंत्र के लिए पूर्वी भारत में विकास की गाथा लिखने का 'मंत्र' था, जिसके आधार पर पांच साल में मोदी सरकार ने विकास के मोर्चे पर देश के पूर्वी हिस्से के लिए वह कर दिखाया जो अकल्पनीय है। हालिया चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत वास्तव में विकास कार्यों पर जनता-जनार्दन की अभिव्यक्ति है। यह जीत एक-दो सफल सियासी रणनीतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के विकास की उन समावेशी नीतियों का परिणाम है जिसमें देश के सभी हिस्सों और खास तौर पर पूर्वी छोर को आजादी के बाद पहली बार बराबर का हक मिला। सरकार के साथ यह भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अथक परिश्रम की पराकाष्ठा की भी विजय है।

सरकार और संगठन समान ध्येय के बावजूद अपनी-अपनी मर्यादाओं से युक्त होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी कार्यशैली से यह सिद्ध कर दिया है कि अब राजनीति 'वंशवाद' 'जातिवाद' और 'तुष्टीकरण' से नहीं, बल्कि 'विकासवाद' की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी। अब दौर 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' का है यानी जो परिणाम देगा, जनता उसे ही शासन करने का मौका देगी। दोहरे चरित्र वाली राजनीति के दिन अब लद गए।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गूंज रहे इस विकासवादी स्वर को समझने के लिए 2019 की इस विजयगाथा को समझना होगा। पूर्वी भारत में देश की एक तिहाई आबादी रहती है। तरक्की के शिखर को स्पर्श करने के लिए अनिवार्य सभी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की उपलब्धता के बावजूद पिछड़ेपन का जितना दंश इस क्षेत्र ने झेला, शायद ही किसी भूभाग ने झेला हो। 2014 में मोदी सरकार ने सर्वप्रथम पिछली सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के नाम पर शुरू किए गए अधूरे कार्यों को संपूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास किया। असम में 21 सालों से लंबित देश का सबसे लंबा डबलडेकर रेल-सह-रोड ब्रिज इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड सुपर हाईवे प्रोजेक्ट पीएम मोदी की 'एक्ट ईस्ट नीति' का ही नतीजा है। 2017 के बजट में सरकार ने पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 13,500 करोड़ रुपये और 2018 में 43 परियोजनाओं पर 9,000 करोड़ रुपये की राशि दी। पूर्वोत्तर में जीवन की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर वहां लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिल चुका है। दुर्गम से दुर्गम गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। साथ ही करीब 30 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया गया।

अवधेश राजपूत

पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ पूर्वी भारत को दक्षिण-पूर्वी एशिया का एनर्जी गेट-वे बनाने पर भी मोदी सरकार ने प्रमुखता से काम किया है। यह अब न सिर्फ पूर्वी भारत, बल्कि देश के शेष हिस्से की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करेगी। असम को दी गई तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन की सौगात हो या फिर प्रधानमंत्री 'ऊर्जा गंगा परियोजना' से पूर्वोत्तर के राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ा जाना, समग्र रूप से यह पूर्वोत्तर के विकास में 'हीरा' (अर्थात हाईवे, इंटरनेट और रेलवे) जड़ने जैसा है।

मोदी सरकार ने जो समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया वह केंद्र-राज्य संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला है। उप्र के बलिया में मई 2016 में जब पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया, तब राज्य में सपा सरकार थी। राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल के साथ भी केंद्र सरकार ने योजनाओं में कभी भेदभाव नहीं किया। यहां दुर्गापुर में रेलवे के 294 किमी रेल खंड का विद्युतीकरण, हिजली-नारायणगढ़ के बीच तीसरी रेल लाइन और जलपाईगुड़ी में 1938 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू कीं। यही वजह है कि बंगाल जैसे राज्य में विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुई।

पश्चिम बंगाल की तरह भाजपा को ओडिशा, झारखंड और असम जैसे राज्यों में भी खूब जनसमर्थन मिला। ओडिशा में केंद्र द्वारा कौशल विकास, जनधन, उज्ज्वला, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का परिणाम यह रहा कि वहां भाजपा अपने वोट प्रतिशत को 38 प्रतिशत तक पहुंचाने के साथ ही आठ सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई। यदि अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों की बात करें तो यहां इससे पहले दिल्ली के नेता केवल लोकसभा चुनाव के वक्त ही दिखते थे, लेकिन पीएम मोदी हर साल पूर्वोत्तर के किसी न किसी राज्य के दौरे पर गए और सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सरकार के लगभग हर मंत्रालय ने विकास के 'पूर्वोदय' के लिए पूर्वी भारत को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। पिछले पांच साल में शायद ही ऐसा कोई महीना रहा हो जब किसी केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में खुद जाकर केंद्र की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट न ली हो। इससे बरसों तक खुद को अलग-थलग महसूस करने वाले लोगों को भी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में रहने वाले दूसरे लोगों की तरह से भारतीय नागरिक होने का अहसास होने लगा।

झारखंड, बिहार के साथ प. बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों की 88 सीटों में से 44 सीटों पर राजग की कामयाबी देश की तरक्की में 'पूर्वोदय' की भूमिका को लेकर की गई उसकी दृढ़प्रतिज्ञा को सिद्ध करती है। भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधताओं का देश है। पीएम मोदी स्वयं पूर्वी भारत की संस्कृति के वैश्विक ब्रांड अंबेसडर बने। वह जिस राज्य में गए उसकी बोली, भाषा और पहनावे को अपनाकर सांस्कृतिक समन्वय का संदेश दिया। इस जीत से मिले संदेश को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही विश्व को भी समझना होगा।

पूर्वी भारत विश्व के लिए आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता का एक ऐसा केंद्र बिंदु बन रहा है जो पड़ोसी देशों के साथ ही पूरे विश्व की शांति-समृद्धि की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों की उपस्थिति भारत के 'पड़ोसी प्रथम' की नीति के साथ वैश्विक नेतृत्व की उसकी क्षमता की एक स्वाभाविक पुष्टि है। बिम्सटेक देशों के साथ भारत की गहरी मित्रता आर्थिक, पर्यटन, जलवायु, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के साथ इन देशों के साथ भारत के संबंधों की सांस्कृतिक प्रगाढ़ता को भी परिलक्षित कर रही है।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

मुसलमानों को डराने का अभियान

निघत अब्बास

मुस्लिमों में डर और नफरत भरने वाली राजनीति के साथ ही मोदी को दुश्मन की तरह दिखाने की भी कोशिश हुई है

जो सच्चा, मददगार, पाक और नेक है वही इंसान है। खुदा ने मुसलमान को इन सभी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इस दुनिया में बहुत लोग भ्रम फैलाने का भी काम करते हैं। यह काम मुसलमानों के बीच भी किया जाता है। देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के जेहन में कई तरह के भ्रम भर रखे हैं। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि इन राजनीतिक दलों का अस्तित्व बना रहे। कांग्रेस ने देश को जाति और मजहब के आधार पर कुछ इस तरह बांटा कि बहुत से मुसलमान कभी यह समझ ही नहीं पाए कि वह सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनका सियासी इस्तेमाल कर रही है। देश ने कांग्रेस को इतना अधिक समय दिया, लेकिन वह मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल ही करती रही। बाद में कांग्रेस की रणनीति अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपना ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मुसलमानों का अस्तित्व उस नींव पर रखना चाहा जहां वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह पहली दफा हुआ जब मुसलमान महिलाओं की एक सबसे बड़ी पीड़ा यानी तत्काल तीन तलाक का हल निकालने की कोशिश की गई। तीन तलाक जैसी निंदनीय प्रथा को खत्म करने का जज्बा इसके पहले किसी भी राजनीतिक दल या सरकार ने नहीं दिखाया। मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करने वाली पार्टियां आती-जाती रहीं, लेकिन किसी ने मुस्लिम महिलाओं की सुध नहीं ली। मोदी सरकार ने न केवल सुप्रीम कोर्ट में तत्काल तीन तलाक के खिलाफ मजबूत दलील पेश की, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए एक विधेयक भी पेश किया। यह विधेयक लोकसभा से पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य उन दलों ने उस पर अड़ंगा लगा दिया जो खुद को मुस्लिम समाज का हितैषी बताते नहीं थकते थे।

यह मोदी सरकार ही थी जिसने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ाया। अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का भी बजट बढ़ाया गया। इसके अलावा अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए शादी शगुन लाई गई। इसके तहत इस समाज की ग्रेजुएट महिलाओं को 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को ध्यान में रखकर उनके लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई। उन्हें विदेश में शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं भी बनीं।

मोदी सरकार की चाहे उज्ज्वला योजना हो या मुद्रा योजना

अथवा शौचालय निर्माण योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को भी मिला। इन योजनाओं में किसी तरह का भेद नहीं किया गया। कोई यह नहीं कह सकता कि इन योजनाओं को लागू करते समय जाति-मजहब का ध्यान रखा गया। ध्यान रखा गया तो केवल इसी बात का कि कौन गरीब है और कौन नहीं।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ भी गरीब मुसलमानों को मिला। मुसलमानों के इन योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद भी विपक्षी दल उन्हें भाजपा से डराते रहे। इन दलों के साथ खुद को सेक्युलर कहने वाले बुद्धिजीवियों ने भी मुसलमानों को अहसास कराया कि वे खतरे में हैं। विडंबना यह रही है कि तमाम मुसलमानों ने इस झूठे खतरे को सच मान लिया। मैं चुनावों के दौरान कई मुसलमान भाई-बहनों से मिली। ये आम नागरिक थे और उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं था। उनसे बातचीत करने के पीछे मेरा मकसद यह जानना था कि आम मुसलमान मोदी सरकार और भाजपा के बारे में क्या सोचता है? इन लोगों से मैंने कुछ देर पारिवारिक बातें कीं और फिर बातों ही बातों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। कई लोगों को इन योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। मैंने सोचा दिक्कत कहां है? दिक्कत इस समाज में पढ़े-लिखे लोगों की तादाद में कमी की है। जाहिर है कि मुसलमानों को अपने नेतृत्व के बारे में सोचना होगा और साथ ही खुद को उस भय से मुक्त करना होगा जो निराधार है।

मुसलमानों ने एक तरह से अपने आप को खुद कमजोर बनाया हुआ है। वे इसलिए कमजोर हैं, क्योंकि वे अपने बेटों और खासकर बेटियों को पढ़ने-लिखने की आजादी नहीं देना चाहते। वे इसलिए भी कमजोर हैं, क्योंकि वे भ्रम को सच मान बैठे हैं। वे इसलिए भी कमजोर हैं, क्योंकि वे उन दलों के बहकावे में आ जाते हैं जो उन्हें भयभीत रखना चाहते हैं। मुसलमानों ने ऐसे दलों को समर्थन देकर अपने को कमजोर बनाने का ही काम किया है। मैंने जब इन लोगों से पूछा कि बीते पांच साल में उन्हें किस तरह की दिक्कत पेश आई है और क्या वे अपने को असुरक्षित पा रहे हैं तो किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था।

ज्यादातर राजनीतिक दलों ने मुसलमानों में डर और नफरत भरने वाली राजनीति नहीं की है, उन्होंने भाजपा और मोदी को मुसलमानों के दुश्मन की तरह दिखाने की भी कोशिश की है। अब जब प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि उन्हें अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतना है तब फिर मुसलमानों को भी सोचना होगा कि आखिर कौन उनका भला सोच रहा है और कौन नहीं? प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही कहा कि जैसे गरीबों के साथ हो रहे छल में हमने छेद किया उसी तरह अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे छल में भी छेद करना है। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों से उनका आशय मुसलमानों से ही है। मुसलमानों के बीच कैसे काल्पनिक भय फैलाया जाता है, इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद ही देखने को मिला। विभिन्न टीवी चैनलों में काम कर चुकी एक महिला पत्रकार ने कहा कि मोदी अपने इस भाषण से अपने समर्थकों को यह संदेश दे रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करना शुरू करो। ऐसे और भी लोग हैं जो इसी तरह का माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि मोदी के फिर सत्ता में आ जाने से अब मुसलमानों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। मुसलमानों को ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए यह देखना होगा कि उन्हें किस राह पर किसके साथ चलना है।

(लेखिका स्वयंसेवी संस्था स्त्री रोशनी की निदेशक एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन चेतना

प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियों का भंडार होता है, किंतु अधिकांश व्यक्ति अनंत शक्तियों के भंडार का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। उनकी ये शक्तियां सोई हुई ही रहती हैं। यहां तक कि उनके जीवन की अंतिम घड़ी भी आ जाती है, लेकिन वे अपनी इन सोई हुई शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते हैं। जीवन का यथार्थ यही है कि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी इन अनंत शक्तियों और असीमित संभावनाओं के बारे में विचार तक नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन की शक्ति का हजारवां हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हां, कुछ ऐसे जरूर हैं जो अपने जीवन की वास्तविक शक्ति का चौथाई या फिर आधे हिस्से का प्रयोग कर पाने में सफल हो जाते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या न के बराबर ही है। इस प्रकार से हमारी बहुत सी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का प्रयोग आधा अधूरा भी नहीं हो पाता है। इसी कारण मनुष्य अपनी स्वयं की आत्मा के समक्ष हीनभावना के साथ जिंदगी व्यतीत करता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा को अपने शरीर की अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर पाता है। उसके शरीर की अग्नि शरीर में बुझी बुझी-सी जलती है। व्यक्ति का सक्रिय और संरचनात्मक जीवन ही उसे इस स्थित से उबार सकता है।

यदि कोई मनुष्य स्वयं दीन-हीन बना रहेगा तो उसके लिए इससे बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं होगा। व्यक्ति का सार्थक प्रयास हर कठिन चुनौती को आसान बना देता है। इसलिए हर एक को प्रयास करने की मनोभावना को विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे स्वयं के प्रयास ही हमें वहां पर पहुंचा देते हैं जहां पहुंच कर हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमें इस प्रकार के प्रयासों के प्रति सदैव सजग रहने की आवश्यकता है।

जिस प्रकार से जमीन को खोदने पर जल स्रोत मिलते हैं उसी प्रकार से जीवन को खोदने पर शक्ति स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए जिस मनुष्य को अपने आप की पूर्णता अनुभव करनी होती है वह सदैव सकारात्मक रूप से सक्रिय सजग और सतर्क रहता है, जबकि अन्य लोग सोच-विचार और तर्क-वितर्क में ही उलझे रहते हैं। सकारात्मक व्यक्ति अपने विचारों को क्रियात्मक रूप में परिणित कर लेते हैं।

वीके जायसवाल

क्यों नहीं दिखते अब जुगनू

अंशुमाली रस्तोगी

बढ़ते प्रदूषण ने जब इंसानों का ही जीना मुहाल कर रखा है तो फिर दूसरे जीव-जंतुओं और जानवरों की क्या बिसात

आखिरी बार जुगनुओं को कब देखा था, मुझे याद नहीं। अब जुगनू हमारी बचपन की यादों और कहानियों में ही बचे रह गए हैं। आज बच्चों से जुगनुओं के बारे में पूछो तो इतना भर कह देते हैं-हां, क्लास की किताब में देखा-पढ़ा था 'लाइट वाले कीड़े' के बारे में! मुझे खूब याद है, जब हम छोटे थे तब कितने ही जुगनुओं को रात के अंधेरे में उड़ता पाते थे। लाइट जलाते-बुझाते नन्हे-नन्हे जुगनू कितने आकर्षक लगते थे। तब जुगनू ही हमारे खेल और मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। एक साथ कई-कई जुगनुओं को हल्की जलती-बुझती लाइट के साथ देखना बड़ा खूबसूरत लगा करता था।

देखते ही देखते जुगनू हमारे बीच से ऐसे गायब हुए कि अब वे शहर तो क्या गांव में भी शायद ही नजर आते होंगे! जुगनुओं को गायब करने के दोषी तो हम ही हैं। निरंतर बढ़ता शहरीकरण, खेतों का खत्म होना, जंगलों-पेड़ों का कटना सिर्फ जुगनुओं को ही नहीं, और भी न जाने कितने जीव-जंतुओं को लील गए हैं। बढ़ते प्रदूषण ने जब इंसानों का जीना मुहाल कर रखा है तो फिर दूसरे जीव-जंतुओं एवं जानवरों की क्या बिसात। हमने जुगनुओं को नहीं, गौरैया को भी अपने बीच से लगभग गायब कर दिया है। अब जोर लगाया जा रहा है कि गौरैया फिर से लौट आए। हर रोज सुबह मीठी तान सुनने वाली कोयल तक अब कम ही नजर आती है। भूले-भटके ही उसकी आवाज कानों में पड़ती है। प्रकृति से खिलवाड़ की होड़ यहीं खत्म नहीं हुई है, यह लगातार जारी है। नदियों-तालाबों को पाट कर रोज नई-नई कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। खेतों को खत्म किया जा रहा है।

अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को हमने कुछ ऐसा बना और बदल दिया है कि अब यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। यह परिवर्तन जितना खतरनाक इंसानों के स्वास्थ्य के लिए है, उतना ही जानलेवा पशु-पक्षियों एवं जीव-जंतुओं के जीवन के लिए भी है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की जद में हम इस कदर आ चुके हैं कि आने वाले वर्षों में धरती के हर प्राणी का जीवन कठिन से कठिनतम होगा। एक दौर हमारे बचपन का ऐसा भी गुजरा है, जब जुगनुओं को रात में देखना आम बात हुआ करती थी। तब किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम इस खूबसूरत जीव को देखने को ही तरस जाएंगे। जो पीढ़ी आगे आ रही है, उसके लिए तो जुगनू संभवतः किस्से-कहानियों में ही रह जाएंगे। जुगनू हर उम्र के व्यक्ति के लिए कौतुहल का कारण रहे हैं। खासकर उनके भीतर से प्रकाश का निकलना। यह भी पढ़ा है कि पुराने जमाने में लोग जुगनुओं को एक डिब्बे में बंद कर उससे रात में राह देखने और स्त्रियां घर को अंधेरे से मुक्त रखने के काम में लिया करती थीं।

जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, इसके अपने वैज्ञानिक कारण हैं। पर हमें उनका यों लाइट की मानिंद जलना-बुझना आकर्षित तो करता ही है। जुगनुओं के साथ बीता बचपन हमेशा यादों में रहेगा। अब जबकि जुगनुओं का संसार विदा ले चुका है शहरों से तो क्या हमें कुछ ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए कि वे वापस आ सकें हमारे बीच, ताकि हम अपने बच्चों को दिखा सकें कि देखो, ऐसा होता है लाइट वाला कीड़ा 'जुगनू'।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अब कांग्रेस को नए अध्यक्ष की जरूरत

'हुआ तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ' शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजीव सचान ने जो विचारणीय प्रश्न खड़े किए हैं, उन पर कांग्रेस के रणनीतिकारों को मंथन करने की जरूरत है। हकीकत को जाने बिना येन-केन-प्रकारेण देश की सत्ता पर काबिज होने की कुचेष्टा में कांग्रेसी कुनबा अंधा हो गया था। इस कुनबे ने मोदी शासन के पिछले पांच वर्षों में हुए जमीनी बदलाव को देखने और समझने की कोशिश नहीं की और 'चौकीदार चोर है' जैसे नारे को गढ़कर मोदी के ईमानदार व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाला। इससे मोदी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कांग्रेस की साख पर बट्टा जरूर लग गया, जिसका नुकसान 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनावों में अपने जीते हुए तीन राज्यों में भी कांग्रेस इसीलिए नाकाम रही। शायद इसी खीज में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मौके का फायदा उठाते हुए अपने बीच के किसी योग्यतम व्यक्ति को कांग्रेस की कमान सौंपकर नेहरू खानदान के नाम पर थोपे गए अध्यक्ष से मुक्ति पा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी से ज्यादा योग्य व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए नेहरू परिवार की अपरिहार्यता के चलते इन योग्य व्यक्तियों को अध्यक्ष की कमान नहीं सौंपी गई। आखिर कांग्रेस कब तक नेहरू खानदान के अयोग्य वारिसों को अध्यक्ष के रूप में ढोती रहेगी? अतः अब समय के सापेक्ष कांग्रेस को इस अंधनिष्ठा से बाहर निकलकर नए सिरे से पार्टी का गठन करके सदन में परिपक्व विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, ताकि भारतीय जनमानस में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक संदेश जा सके।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

परिवारवाद से निकलना होगा बाहर

एक बार लोकसभा में बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। किंतु राहुल गांधी आत्ममंथन के बजाय त्यागपत्र देकर आलोचनाओं से बचना चाहते हैं। दरअसल 17वीं आम चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। निःसंदेह राहुल अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की दिशा व दशा के लिए उत्तरदायी हैं। त्यागपत्र किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें परिस्थितियों पर गहन चिंतन करना होगा। राजनीति में गलतियां होती रहती हैं और राहुल ने भी की हैं, उनका वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला अमेठी को रास नहीं आया। इससे यही संदेश गया कि राहुल को अमेठी वालों पर भरोसा नहीं रहा। परिणामस्वरूप उन्हें अमेठी से पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरी भूल कांग्रेस महागठबंधन की अवधारणा को मूर्त रूप नहीं दे सकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए अनुरोध करती रही, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। नतीजा यह निकला कि दिल्ली की सातों सीट भाजपा की झोली में जा गिरी। यदि कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन बनता तो बेहतर परिणाम की अपेक्षा की जा सकती थी। कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि अब उसके पास नेहरू या इंदिरा गांधी जैसी छवि के नेता नहीं हैं, जो अपने बलबूते पार्टी को सत्ता के शिखर पर बैठा दें। इ